farmers and this premia subsidy is shared equally by Central and participating State Governments.

(c) and (d) Owing to nominal premia rates i.e. 2% for foodgrain crops and 1% for pulses and oilseeds and also due to frequent occurrence of natural calamities, Government is losing Rs. 5.73 on every Rupee of premium earned in kharif 1995 season.

(e) and (f) A Concept Paper containing suggestions for revision of the existing Crop Insurance Scheme has been circulated to all the Members of parliament. After receiving their reactions a formal proposal for revision of the scheme will be initiated.

Guidlines for production of fertilizers

214. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there are any guidelines set by Government which the fertilizer companies have to follow while fixing the price of the fertilizers produced by them;

(b) if so, the details of the machinery to check whether the guidelines are being followed or not; and

(c) if not, whether government propose to set any guidelines in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI SISRAM OLA): (a) to (c) At present, urea is the only fertilizer covered by statutory price control. Urea is required to be sold at a uniform price of Rs. 3320 per tonne, excluding local taxes. The enforcement machinery of the State Governments ensures that urea is sold at the Statutory price.

The prices of all other fertilizers have been decontrolled. The Government of India has, however, extended a special concession to the farmers on sale of phosphatic and potassic fertilizers. The State Governments have been requested to ensure that the full benefit of the special concession is passed on to the farmers. With this end in view, the State Governments have to negotiate the prices of these fertilizers with the manufacturers/suppliers concerned.

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़

215. प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष भारी वर्षा और बाढ़ से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) इससे कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी कई बार हुई थीं; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जान-माल की हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1996 के दौरान चक्रवात, भारी वर्षा एवं बाढ़ से 1574 लोगों की मृत्यु हुई है, 7.18 लाख मकानों को नुकसान हुआ है तथा 17.95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफानों के पर्यवेक्षण, संसूचन, निरीक्षण एवं उनके आने की पूर्व सूचना एवं आवश्यक चेतावनी जारी करने के उद्देश्य से चक्रवात चेतावनी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों के निर्दिष्ट स्थानों तक भी चक्रवात चेतावनी को जल्दी एवं सीधे पहुंचाने के लिए इनसैट उपग्रहों की मदद ली जाती है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्रसारण के माध्यम से भी चक्रवात संबंधी चेतावनी दी जाती है। केन्द्रीय जल आयोग राज्य सरकारों के निकट सहयोग से एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली का प्रचालन करता है। जान-माल की क्षति को न्यूनतम रखने के लिए राज्य सरकार विभिन्न उपाय करती है। जिसमें संभावित बाढ़ वाले क्षेत्रों से लोगों को हटाया जाना भी शामिल है।